प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 02 – 09 सितम्बर 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या टीसीपी का प्रस्तावित संशोधन संभावित निवेशकों के दबाव का परिणाम है

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार की टीसीपी के तहत प्लानिंग और साडा क्षेत्रों में शामिल किये गये ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से बाहर करने पर विचार कर रही है। इसके लिये आईपीएच मंत्री महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मन्त्रीयों की एक उप समीति बनाई गयी है। कहा गया है कि इस उप समिति के पास ग्रामीण क्षेत्रों से इस आशय के 120 प्रस्ताव आये हैं। पिछले दिनों प्रदेश सचिवालय में हुई इस उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के लिये जन सुनवाई की जायेगी। यह जन सुनवायी शिमला मे सुरेश भारद्वाज, कुल्लु – मनाली में गोविन्द ठाकुर और मण्डी में स्वयं महेन्द्र सिंह ठाकुर करेंगे। शिमला में हुई उप समिति की बैठक में इन मन्त्रीयों के अतिरिक्त विधायक सुखविन्दर सिंह सुक्खु, विधायक अनिरूद्ध सिंह और सचिव टीसीपीसी पालरासू और कुछ अन्य अधिकारी भी शामिल रहे हैं। इस बैठक में शिमला को लेकर यह सुझाव आया है कि यहां भवनों की ऊंचाई 21 मीटर तय कर दी जानी चाहिये। शिमला, मण्डी और कुल्लु, मनाली के अतिरिक्त प्रदेश में और कहां पर इस उप समिति की बैठकें होंगी तथा और कहां – कहां से प्रस्ताव आये हैं यह अभी सामने नही आया है।

स्मरणीय है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हुए अवैध निर्माणों का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सुर्खीयों में रहे हैं। अदालत के आदेश पर ऐसे निर्माणों के बिजली पानी तक काटे गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय से ही एक मामला शुरू में एनजीटी में गया था और उसके बाद ही एनजीटी ऐसे मामलो पर गंभीर हुआ। कसौली का मामला एनजीटी के आदेशों का ही परिणाम है। कुल्लु में मन्त्री महेन्द्र सिंह ने एनजीटी के आदेशों पर अपने होटल का अवैध निर्माण स्वयं गिराया है। योगेन्द्र सेन की याचिका पर दिये गये फैसले में एनजीटी ने अढ़ाई मंजिल तक ही निर्माण सीमा इसलिये तय की है क्योंकि शिमला ही नही हिमाचल प्रदेश का 80% भाग संवदेनशील भूकंप जोन में आता है। आपदा प्रबन्धन के तहत सरकार द्वारा किये गये अपने अध्ययन की रिपोर्ट में यह दर्ज है कि यहां पर हल्का सा भी भूकंप का झटका आने पर 30,000 लोगों की जान जायेगी। इसी अध्ययन के बाद सचिवालय में सचिव स्तर की एक कमेटी गठित की गयी थी और पहली बार वर्ष 2000 में शिमला में सरकारी और गैर सरकारी निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। एनजीटी के 16-11-2017 के फैसले का आधार पर इसी सचिव कमेटी की सिफारिशें बनी हैं और फैसले में यह विशेष रूप से दर्ज भी है। इसी फैसले में निर्माणों को नियमित करने के लिये 5000 से 10,000 रूपये प्रति वर्ग फुट जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी तक में प्रदेश में अवैध निर्माणो का आंकड़ा 35000 तक आया है। लेकिन सरकार आज भी सदन में यही जानकारी दे रही है कि अवैध निर्माणों के केवल 8782 मामले ही उसके सामने आये हैं। इनमें भी नगर क्षेत्रों के 5444 तथा नगरों से बाहर के 3338 मामले ही हैं। नगर निगम शिमला में एनजीटी के फैसले के बाद केवल 14 नये और 264 संशोधित मामले स्वीकृति के लिये आये हैं। लेकिन अवैध निर्माणों को लेकर निगम मौन रहा है जबकि पिछले दिनों उच्च न्यायालय में आये एक मामले में यह संख्या 8300 कही गयी है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में अवैध निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी आपदा की घड़ी में इनके कारण हजारों की संख्या में जान माल का नुकसान हो जायेगा। इसी नुकसान की आशंका निर्माणों पर रोक और उन्हे अढ़ाई मंजिल तक सीमित किया गया है। लेकिन जिस ढंग से टीसीपी में संशोधन की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग और साडा से बाहर करने की तैयार की जा रही है। उससे यह सवाल उठता है कि क्या संशोधन के बाद यहां पर बहुमंजिलों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। आखिर किसके लिये इस माध्यम से यह सुविधा देने की तैयारी हो रही है। अभी शिमला के 30 किलोमीटर के दायरे में ज़मीन मांगने के 26 आवदेन आये हैं जिनमें से आठ तो सीधे आरएसएस से ही ताल्लुक रखते हैं। इसी किलो मीटर के दायरे में कुछ मंत्रीयों और अधिकारियों की भी ज़मीने हैं। मन्त्रीयों की जो उप समिति बनी है शायद उसके भी सदस्य की जमीन इस दायरे में आती है। एनजीटी के फैसले के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गयी थी लेकिन शायद वहां से इसमें कोई राहत नही मिली है। फिर भवन निर्माण क्षेत्र में आने वाले संभावित निवेशकों की ओर से भी शायद यह दबाव है कि निर्माण पर लगी अढ़ाई मंजिल की शर्त को हटाया जाये। क्योंकि कोई भी भवन निर्माता अढ़ाई मंजिल का निर्माण करके इसमें लाभ नही कमा सकता। चर्चा है कि अभी पंजीकृत हुए एक गुप्ता भवन निर्माता ग्रुप ने शिमला के 30 किलो मीटर के दायरे में सौ बीघा से अधिक ज़मीन की खरीद की है लेकिन एनजीटी के मौजूदा फैसले के तहत यह निर्माण लाभकारी न हों इसी आशंका के चलते ऐसे लोगों के दबाव में आकर टीसीपी में संशोधन का रास्ता अपनाया गया है और उसमें शिमला, मण्डी तथा कुल्लु मनाली पर ही फोकस रखा गया है। इस प्रस्तावित संशोधन पर पर्यावरण प्रेमियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है यह आने वाले दिनों में सामने आयेगा।

यह हैं 26 आवेदक

Sr. No.	Name of Organization and Individuals		Nature of Land
1	Smt. Nancy Sharma, President Aashritha, NGO, Lower Kuftadhar Shimla.	--	-
2	Sh. Kulvinder Singh Chairman, Chapslee Welfare Society, Laxmi Bhawan Chapslee Estate, Lakkar Bazar, Shimla.	156-25 Sq. meter	जंगल बिला किस्म
3	Sh. Devi Roop, President, Himachal Shiksha Samiti, Himrashimi Prisar, Vikar Nagar, Shimla-9	5071-01 Sq. meter	जंगल बिला किस्म
4	Sh. Ajay Kumar, President, Matri Bandana Sansthan, Dr. Hedgebar Bhawan, Nahba.	715 Sq. meter	चरागाह द्रख्तान
5	Sh. Ram Rishi Bhardwaj, Mahamantri, Bhartiy Govansh Rakshan Sanvardhan Parishad		
6	Sh. Kamlesh Kumar Thakur S/o Late Sh. Moti Ram Village Charoli, P.O Anandpur, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla.		
7	Sh. Kedar Singh, R/o Shanti Niwas, Uday Colony, Chakrel Road Bhattakufer Shimla.	650 Sq. meter	चरागाह द्रख्तान
8	Sh. Dinesh Sharma State Secretary, (BMS), Om Bhawan, IInd Floor Himlan Shimla.	600 Sq, meter	चरागाह द्रख्तान
9	Sh. Chander Prakash S/o Paras Ram & OM Prakash S/o Ram Krishan R/o Patti PO. Koti, Sub-Tehsil Junga, District Shimla, H.P	14 Biswa	चरान्द वृक्ष
10	Sh. Naresh Chauhan, S/o Sh. Kali Ram Chauhan, PO Makrog, Kohbaag, Sub-Tehsil Junga, District Shimla	3 Bigha	
11	President, Virasat Sanskriti uthan Samiti, Sarswati Sangeet Shiksha Kendar, Baub Ram Building New Totu, Shimla-171001.		चरागाह बिला द्रख्तान
12	Sh. Devinder Sharma, S/o Sh. Jeet Ram, Village Parech, PO Ghanati, District Shimla.	1 Biswa	चरान्द
13	Smt. Yasmin D/o Rashid Ahamad R/o Eidgah Colony Lakkar Bazar Shimla	1 Biswa	
14	Vishwa Hindu Vidyapeeth, Vasudhavarn-A42-43 Paravran Complex, New Delhi-110030	25 Acres	
15	Sh. Krishna Kumar Sharma (Nagar PRamukh S/o Late Sh. Shanti Swaroop Sharma, R/o Vivekananda) Kendra Kanyakumari, Branch Shimla, Nabha Estate Tehsil Shimla District Shimla.	194.42 Sq metr	
16	Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Late Sh. Nanak Chand R/o 3rd Floor, Nanak Niwas, Bharari Shimla	4 biswa	
17	Dr. Vivek Gupta, Course Chairman, Organizing Secretary, 7th Indo- European Course on revascularization (IECR) A 137, Sarita Vhair, New Delhi.	50 Acres	
18	Sh. Kapoor Singh, CEO-cum Secretary, the Maloothi Fruits Flowers & Vegetable Growers Marketing Co-op Society Ltd. VPO Maloothi District Shimla.	00-06-38 hectare	चरागाह बिला द्रख्तान
19	Sh. Surinder Kumar, President, Sh. Kamanapurni Gaushala Simiti Totu Shimla.		
20	Sh. Narender Pal S/o Rattan Chand Pal, Sunrise Cottage Panthaghati Shimla.	750. Sq. meter	चरागाह द्रख्तान
21	Sh. Gopal Jhilta, (General Secy) Sahakar Bharti, HP HQ Sheetal Sadan, Lower Shiv Nagar, Kasumpati Shimla-4		
22	M/s Sonia Sharma R/o House No. 21, type-IV GAD Colony, Kasumpati Shimla	0-04-06 hectare	चरागाह द्रख्तान
23	Smt. Banti Devi D/o Sanu Ram, Block A-1, type 1 Set No. 2 Nabha Estate, Shimla-4	04 Biswa	
24	Sh. B.D Pathak, President, Mandi Mittar Mandal, Dream House, HP Housing Colony Jakhu, Shimla-2	00-49-42 hectare	चरागाह बिला द्रख्तान
25	M/s Dhary Jamwal D/o Sh. Vijay Jamwal r/o Jamwal Deco, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi	00-08-84 hectare	चरागाह बिला द्रख्तान
26	Sh. Bodh Raj Sharma, President, Dr. Hedegewar Samarak Samiti, Nabha Shimla	793-28 hectare	जाये सरकार

राज्यपाल ने रोपा दुर्लभ पौधा जिन्को

शिमला/शैल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दुर्लभ पौधा 'जिन्को' रोपित किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर सत्यावती मिश्र

ने भी जिन्को पौधा रोपित किया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रकृति की दृष्टि से समृद्ध है और इसे संजोए रखने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए ताकि प्रदेश की हरियाली और पर्यावरण को बरकरार रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि जिन्को एक जीवित जीवाश्म है, जो 270 मिलियन वर्ष पुराना है। यह लगभग एक हजार वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों जैसे दमा, अल्जाइमर, कैंसर, मानसिक रोग और रक्त संचार इत्यादि के उपचार में किया जाता है।

राज्यपाल ने इससे पूर्व, इस दुर्लभ पौधे को बागवानी शोध एवं विस्तार केन्द्र क्रेगनैनो (मशोबरा) में भी लगाया था। उन्होंने वन विभाग से ऐसे दुर्लभ पौधों की प्रजातियों व औषधीय पौधों को रोपित करने पर बल देने का आह्वान किया है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
***** Notice Inviting Tender *****

Sealed item rate tender on form No. 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer, HP PWD Division Tanda at Nagrota Bagwan on behalf of Governor of Himachal Pradesh** for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD (B & R) whose registration stood renewed as per revised rules so as to reach in his office on or before on **11.10.2019 up to 11:00 A.M.** And the same shall be opened on the same day at **11:30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender form can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on **10.10.2019 up to 4:00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **09.10.2019 up to 12:00 noon.** The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account of the Post Office /Time Deposit account/FDR in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, HP PWD Division Tanda at Nagrota Bagwan.
The conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Sr..No. Name of Work	Estimated cost	Earnest Money	Time period
1. Restoration of rain damages at Hachichik Bag Nehar Palachaklu road Km 0/000 to 0/600 (SH:-C/O U-Shape drain with edge wall at RD 5/300 to 5/600)	438165/-	8800/-	Three months
2. Restoration of Rain damages on DSS Kandi road (SH:-C/O R/Wall at RD 13/570 to 13/600)	342679/-	6900/-	Two months
3. Restoration of Rain damages DSS Kandi road Km 8/400 to 8/605 (SH:-C/O U-shape drain at RD 8/400 to 8/600)	226219/-	4600/-	two months
4. Improvement of black spots on DSS Kandi road Km 20/000 to 33/100 (SH:-Improvement of road width by providing R/Wall at RD 27/515 to 27/8530)	279786/-	5600/-	Two months
5. Improvement of Black spots on DSS Kandi road Km 20/000 to 33/100 (SH:-Construction of crash Barriers at RD 27/500 to 27/700).	392144/-	7900/-	Two months
6. Restoration of rain damages on Mangrella Luhna Har road Km 0/000 to 5/000 (SH:-C/O R/Wall at RD 3/180 to 3/195)	208724/-	4200/-	Two months
7. Improvement of Black spot on link road Luhna to Baroh road (SH:- C/O R/wall RD 0/425 to 0/447)	306787/-	6200/-	Two months
8. C/O pucca path in G.P. Rajiana in The Nagrota Bagwan in Distt Kangra (SH:-Providing and laying cement concrete pavement from RD 0/000 to 0/053 (Deposit Work)	140226/-	2900/-	One month
9. A/R & M/O Samloti to Mumta Khas road Km 0/000 to 2/000 (SH:-C/O Road side plate form by providing cement concrete edging both sides)	269383/-	5400/-	One month
10. Restoration of rain damages on Samloti Sarotari road Km 0/000 to 4/600 (SH:-Protection work of existing 4.00 mtr span culvert at RD 2/905 by providing O/S & D/S toe walls flooring work inbed and C/O wing walls at RD 2/890 to 2/900 & 2/908 to 2/913)	259520/-	5200/-	Two months
11. Restoration of rain damages on Sadoon to Akrana road Km 0/000 to 3/180 Under SCSP (SH:-Protection work to existing house by providing breast wall at RD 2/150 to 2/166)	399004/-	8000/-	Two months
12. Restoration of rain damages on upper Jamula to Lower Jamula road Km 0/000 to 1/000(SH:-C/O Breast wall at RD 0/430 to 0/450 & improvement of road by providing retaining wall at RD 0/650 to 0/670)	365905/-	7400/-	Three months
13. Restoration of Rain damages on Upper Jamula to Lower Jamula road Km 0/000 to 1/000 (SH:-Providing and laying WBM Grade-I & Cement Concrete pavement at RD 0/300 to 0/450)	478351/-	9600/-	Two months
14. C/O link road from Village Malan to Ghar Mata temple (Portion Malan to Guhrehra Km 0/0 to 4/550) (SH:-Providing and laying 1/500 to 2/000)	114370/-	2300/-	One month
15. Restoration of rain damage on Upper Jamula road Km 0/000 to 1/000 (SH:-Providing and Laying Bituminous concrete at RD 0/000 to 0/100 & 0/600 to 0/750)	168281/-	3400/-	One month
16. C/O Govt. B Pharmacy College at Nagrota Bagwan in Distt Kangra (SH:-Landscaping)	3,90,000/-	7800/-	Three months

Terms &Conditions:-
1. The contractor/firm should be registered as or dealer GST No.
2. The intending contractor / firm have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holidays the same shall be processed on next working day.
4. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.
5. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand.
6. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-1865/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

सरकार माताओं और शिशुओं को पर्याप्त पोषाहार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ और पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत 21वीं शताब्दी में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, परन्तु देश की कुछ आबादी उचित पोषण से वंचित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने नवजात शिशुओं, धात्री और गर्भवती महिलाओं को उचित आहार और पोषण उपलब्ध करवाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका श्रेय महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय, पंचायती राज संस्थाओं और धरातल पर क्रियाशील संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जाता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पोषण अभियान का शुभारम्भ गत वर्ष मार्च में झुनझुनू राजस्थान से किया था। सरकार नवजात शिशुओं को पोषक आहार प्रदान कर स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शिमला, ऊना, कांगड़ा और कुल्लू जिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान 2018-19 के लिए पुरस्कार प्राप्त किए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1800 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1100 रुपये और सहायिकाओं को 900 रुपये का प्रति माह का अतिरिक्त मानदेय दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यवेक्षकों के पद से बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति करने के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमों में 25 प्रतिशत का प्रावधान किया है ताकि पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सके।

उन्होंने दिव्यांग बच्चों जिन्होंने मार्च, 2019 में आबुधाबी में आयोजित विशेष ओलम्पिक वैश्विक ग्रीष्मकालीन प्रतिस्पर्धा के दौरान पदक हासिल किए थे को 5.25 लाख रुपये के नकद ईनाम वितरित किए। उन्होंने जिला ऊना के रघुनाथ सिंह को 1.25 लाख रुपये और जिला बिलासपुर के शुभम को साईकलिंग के लिए एक लाख रुपये का नकद ईनाम, जिला मण्डी की निशा धवन को एथेलेटिक्स के लिए 75 हजार रुपये, जिला बिलासपुर की पूजा कुमारी को पॉवर लिफ्टिंग के लिए 75 हजार रुपये, जिला मण्डी के विनोद कुमार और अभिषेक कुमार को बॉलीबाल के लिए 50-50 हजार रुपये और जिला मण्डी के चिराग को बास्केटबॉल के लिए 50 हजार रुपये के पुरस्कार वितरित किए।

उन्होंने राज्य में पोषण अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निदेशक ग्रामीण विकास राकेश कंवर, निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा, निदेशक ई.एस.ओ.एम.एस.ए. हंस राज चौहान और विशेष सचिव वित्त राजेश शर्मा को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आई.सी.डी.एस. केन्द्रों को भी उनके

योगदान के लिए सम्मानित किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के गतिशील नेतृत्व में समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षो में समाज के पिछड़े वर्गो के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह ने कहा कि हाल ही में राज्य के तीन जिलों शिमला, सिरमौर और मण्डी को बेटी बचाओ, बेटी पढाओ और पोषण अभियान के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 14 से 21 मार्च तक आबुधाबी में आयोजित विशेष ओलम्पिक वैश्विक ग्रीष्मकालीन प्रतिस्पर्धा के दौरान प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने पदक हासिल किए। उन्होंने विभाग की विभिन्न गतिविधियों की पावर प्वाईट प्रस्तुति भी दी।

राष्ट्रीय पुरूष मुक्केबाजी प्रतियोगिता शिमला में

शिमला/शैल। परिवहन, वन, युवा सेवा एवं खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 4 से 10 अक्तूबर, 2019 तक शिमला में चौथीं विशिष्ट वर्ग की राष्ट्रीय पुरूष मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताहभर चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलिम्पिक, एशियन गेमज और वैश्विक स्तर के मुक्केबाज भाग लेंगे।

उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों, मुक्केबाज और अन्य खेल संस्थाओं और निजी भागीदारों जैसे शिमला होटलियर एसोसिएशन इत्यादि से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रीय भागीदारी से सहयोग करने का आग्रह किया ताकि मुक्केबाजों व इस प्रतियोगिता में आने वाले अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति व अच्छी मेहमान नवाजी का अनुभव हो, जिसके लिए हिमाचल वासी प्रसिद्ध हैं। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का हरसम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता एक बड़ा आयोजन है, जो प्रदेश को अन्य राज्यों से कठिन प्रतिस्पर्धा के बाद प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि लोगों और पर्यटकों को इस पर्वतीय प्रदेश में उच्च श्रेणी की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता देखने का यह एक अच्छा अवसर मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) के अध्यक्ष राजेश भण्डारी ने कहा कि मुक्केबाल प्रदेश का एक लोकप्रिय खेल है और कई मुक्केबाजों ने देश व प्रदेश के लिए कई सम्मान हासिल किए है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ.वाई.एस.परमार, शान्ता कुमार और प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल के दौरान भी शिमला में पांच बार राष्ट्रीय स्तरीय मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। उन्होंने कहा कि 'सेवाएं-रेलवे, थल, वायु और जल सेना' हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मणिपुर, असाम, दिल्ली, पंजाब, चण्डीगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा और आन्ध्र प्रदेश ने पहले से ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की विजेता सेवाएं और उप विजेता रेलवे और हरियाणा के बीच प्रथम स्थान हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला होगा। हिमाचल के मुक्केबाज आशीष शर्मा जो वर्तमान में 75 किलोग्राम मध्य भार वर्ग (मिडल वेट) के नम्बर-1 स्थान पर है, भी इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भाग लेंगे। एचपीबीए के महा सचिव एस.के. शाण्डिल ने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश की 38 टीमों के लगभग 300 मुक्केबाज भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि दो मुक्केबाजी रिंग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्रातः, दोपहर और सायंकाल तीन सत्र में मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।

केन्द्र द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आतंरिक व्यापार विभाग (सीडीपीआईआईटी) ने 7-8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के लिए 5 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता स्वीकृत की है।

मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में, सीडीपीआईआईडी के निदेशक ने बताया कि इस राशि को संकल्पना खाका बनाने हेतु और सम्पूर्ण आयोजन की योजना, अधोसंरचना का सृजन, क्षेत्रीय स्तर पर उद्घाटन, समापन तथा तकनीकी सत्रों के आयोजन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण और 1000 प्रतिनिधियों के आवास, परिवहन और प्रचार-साहित्य जैसे पांच घटकों के लिए स्वीकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से इस विषय को उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के लिए पांच करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के लिए तीन नागरिक सेवाएं की आरम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नगर निगम शिमला में तीन गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा (जी2सी) का शुभारम्भ किया। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इन सेवाओं में ऑनलाईन गारबेज चार्जिज कलैक्शन एप्लीकेशन, ऑनलाईन बिल्डिंग प्लानिंग एप्लीकेशन और रैन्ट और लीज एप्लीकेशन शामिल हैं, जिनके माध्यम से नगर निगम में 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एप्लीकेशनज का उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, अधिक दक्षता, निष्पक्षता और लोगों को सेवाएं एवं जानकारी को उपलब्ध करवाने में तेजी, बिचौलियों को हटाना, निगम स्तर पर जी2सी सेवाए प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं कुशल इन्टरफेस प्रदान करने के साथ नागरिकों को किफायती और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इन सेवाओं के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रणाली की सुविधा सुनिश्चित होंगी, जिससे लोगों को नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से नागरिक अपने भुगतान के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कहा कि बिल्डिंग प्लानिंग परमिशन एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को उनके भवनों के नक्शों को स्वीकृत करवाने के लिए सुविधा प्राप्त होगी। उन्हाने कहा कि स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी मापदण्ड इस एप्लीकेशन के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएंगे और भवन मालिकों को उनके नक्शों के सम्बन्ध में एक क्लिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जनता को पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है।

फिजियोथैरेपिस्ट के रिक्त पद जल्द भरे जायेंगेः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सभी जिला अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट के पदों को भरेगी। इसके अतिरिक्त किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलावा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथैरेपिस्ट का एक अतिरिक्त पद भी सृजित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व फिजियोथैरेपिस्ट दिवस के अवसर पर इंडियन फिजियोथैरेपिस्ट ऐसोसिएशन के हिमाचल चैप्टर तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'हिमक्लेव-2019' के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि की भागदौड़ एवं तनावयुक्त जीवन में फिजियोथैरेपिस्ट का महत्व और भी अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट चोटिल व्यक्तियों को शारीरिक क्रियाओं और अन्य थैरेपियों के माध्यम के अतिरिक्त साईकोमैटिकली रूप से स्वस्थ होने में लोगों की सहायता करते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश फिजियोथैरेपिस्ट परिषद के गठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल में सड़क दुर्घटनाओं की आवृति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक रहती है जिसके दृष्टिगत फिजियोथैरेपिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी छः मेडिकल कालेजों में फिजियोथैरेपिस्ट के 3-3 पद भरने की घोषणा की ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए वृद्धाश्रमों में फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं प्रदान करने की पहल की है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में फिजियोथैरेपिस्ट के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आर.डी.धीमान ने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं।

इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट ऐसोसिएशन के हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष डा. अनूप कुमार ने इस अवसर पर एसोसिएशन की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा अपनी मांगों से मुख्यमंत्रे को अवगत करवाया।

इस अवसर पर फिजियोथैरेपिस्ट एसोसिएशन की ओर से फिजियोथैरेपी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा.ए.के. गुप्ता, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. रवि शर्मा, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के प्रधानाचार्य डा. रंजना राव, पदमश्री डा.ओमेश भारती, एसोसिएशन के हिमाचल चैप्टर के महासचिव डा. नागेश शर्मा, कोषाध्यक्ष डा. विजय भारद्वाज, संयुक्त सचिव डा. अरूण वर्मा तथा संगठन सचिव डा. पारस सहगल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से 1700 लोगों को मिलेगा रोजगार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार और दो कम्पनियों के बीच में 1000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

600 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन प्रदेश सरकार और मै. रिन्यू एनर्जी

प्राईवेट लिमेटिड के बीच में किया गया, जिसमें कम्पनी के निदेशक प्रभात कुमार मिश्रा ने प्रदेश में 150 मेगावाट की हरित ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में 2021 से उत्पादन शुरू होना प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

दूसरा 400 करोड़ का समझौता ज्ञापन सरकार व मै. सीएसई डवेल्पमेंट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के बीच में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा नवीकरण उत्पादन के लिए कम्पनी की ओर से निदेशक बिजनैस डवेल्पमेंट एण्ड हैड ओपन असैस विक्रम मदान ने किया। इस परियोजना के पूरा होने से लगभग 700 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा संसाधन प्रबोध सक्सेना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इन परियोजनाओं से सीधे तौर पर लगभग 1700 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे तथा राज्य को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध होगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इन कम्पनियों को आवश्यक अनुमति व मंजूरी देने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक तकनीक के प्रयोग का प्रयास किया जाएगा। इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ऊना व कांगड़ा जिला में पहले ही भूमि का चयन कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 99533 मेगावाट नवीकरण सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य को 2022 तक 776 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा गया है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, विशेष सचिव एमपीपी और पॉवर हेम राज बैरवा, प्रबन्ध निदेशक जेबी पॉवर क्लीन टैक सोलर एनर्जी के सहयोगी गरीश भयाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयासरतः सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास

कर रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में भूमि चयन के लिए एक शोध समिति तथा शैक्षणिक पहलुओं के लिए एक शैक्षणिक समिति गठित की जाएगी।

शिक्षा मंत्री संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों से आए प्रमुखों तथा शिक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा न केवल एक प्राचीन, शुद्ध व सम्पन्न भाषा है बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास व परम्पराओं की परिचायक भी है। संस्कृत के विद्वानों ने समाज के कल्याण के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने दृष्टिपत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया था तथा इस दिशा में सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उचित स्थान की खोज की जाएगी, जहां संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता होगी। इसके अतिरिक्त गठित की जाने वाली समितियां विश्वविद्यालय के स्वरूप, प्रारूप तथा आर्थिक पक्ष पर भी विचार करेंगी।

प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पन्त ने कहा कि संस्कृत भाषा में हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां समाहित है। प्रदेश सरकार संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि संस्कृत के विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा छात्रों को प्रदेश में ही शिक्षण और पाठन के अवसर प्राप्त हो, जिससे संस्कृत भाषा के साथ-साथ हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

किसानों की सुविधा के लिए किया गया 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' में बदलाव

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' में बदलाव किया है। अब इस योजना में सोलर फैंसिंग के अलावा कांटेदार बाड़ लगाने का भी प्रावधान किया गया है। यह कदम किसानों की मांग व सुझावों को देखते हुए उठाया गया है।

प्रधान सचिव कृषि ओंकार चन्द शर्मा ने बताया कि बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों व बन्दरों से फसल को बचाने के लिए शुरू की गई खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत अब कांटेदार तार/चेनललिंक बाड़बन्दी के लिए 50 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान किया गया है और 70 प्रतिशत उपदान कंपोजिट बाड़बन्दी के लिए किया गया है। इस वर्ष इस योजना पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना में किसानों को पहले ही सौर ऊर्जा बाड़बन्दी के लिए 80 प्रतिशत व समूह में खेतों की बाड़बन्दी करने के लिए 85 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 27 दक्ष सेवा प्रदाता कंपनियां को सूचीबद्ध किया गया है। लाभार्थी अपनी स्वैच्छानुसार किसी भी कम्पनी का चुनाव कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण के उपरान्त ही इस योजना के तहत किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा कहा कि इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने को कहा है।

जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर–उधर देखे उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें.....चाणक्य

सम्पादकीय

भत्ता बढ़ौत्तरी पर उभरे विरोध का अर्थ

इस बार प्रदेश के माननीयों के भत्ते बढ़ाये जाने पर जनता में रोष और विरोध के स्वर देखने को मिले हैं। यह बढ़ौत्तरी पहली बार ही नही हुई है लेकिन विरोध पहली बार हो रहा है। इस विरोध के बाद भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धमूल की प्रतिक्रिया आयी है। धूमल ने कहा है कि जब हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं तब यदि विधायक अपने भत्ते बढ़ायेंगे तो विरोध तो होगा ही। धूमल की प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमन्त्री जयराम का ब्यान आया है कि वेतन भत्ते तो वीरभद्र और धूमल की सरकारों मे भी बढ़ाये गये हैं तो फिर इसी बार यह विरोध क्यों? जनता में उभरे विरोध के बाद भाजपा के एक विधायक मनोहर धीमान ने भी यह बढ़ौत्तरी लेने से इन्कार कर दिया है। जब सदन में इस विधेयक पर चर्चा हुई थी तब केवल मात्र सीपीएम के विधायक राकेश सिंघा ने इसका विरोध करते हुए इसे वापिस लेने की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने न केवल इसका समर्थन बल्कि इसके पक्ष में जबरदस्त तर्क भी रखे। शायद उस समय कोई भी माननीय यह अनुमान ही नही लगा पाया कि जनता इस बढ़ौत्तरी का ऐसा विरोध करेगी। इसी विरोध का परिणाम है कि मुख्यमन्त्री को यह कहना पड़ा है कि यदि विधायक लिखकर देंगे तो सरकार इस पर पुर्नविचार करने को तैयार है। यह आने वाला समय बतायेगा कि विधायक लिखकर देते हैं और यह विधयेक वापिस हो पाता है या नही। क्योंकि मुख्यमन्त्री ने अपने से पलटकर यह जिम्मेदारी विधायकों पर डाल दी है।

जब हर मुख्यमन्त्री के कार्यकाल में ऐसी बढ़ौत्तरीयां होती रही हैं और तब इसका कभी न कभी न तो सदन के अन्दर विरोध हुआ और न ही सदन के बाहर जनता में। फिर इसी बार यह विरोध क्यों और इस विरोध का अर्थ क्या है। यह समझना ही इस विरोध का केन्द्र बिन्दु है। आज राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन चुका है क्योंकि उत्पादन में लगातार गिरावट आती जा रही है। 2014–15 के मुकाबले आज जीडीपी में 3% की गिरावट आ चुकी है। इसमें सबसे रोचक तथ्य यह है कि जब नोटबंदी लागू करते समय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने देश से पचास दिन का समय मांगा था और यह दावा किया था कि पचास दिन में सबकुछ ठीक हो जायेगा। इस दावे के साथ यह भी कहा था यदि इस फैसले में कोई गलती निकलती है तो वह जनता द्वारा किसी भी चौराहे पर सज़ा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन नोटंबदी पर आई आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय 15.44 लाख करोड़ की करंसी चलन मे थी जो आज बढ़कर 21.10 लाख करोड़ हो गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नोटबंदी की आड़ में बड़े स्तर पर कालाधन सफेद होकर फिर उन्हीं हाथों के पास जा पहुंचा है जिनके पास पहले था। आज भी 3.17 लाख करोड़ के नकली नोट बाज़ारा मे आ चुके हैं।

नोटबंदी से न तो कालाधन चिन्हित हो पाया है और न ही उसके बाद जाली नोट बंद हो पाये हैं। उल्टा तीन लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। जब नरेन्द्र मोदी ने देश से पचास दिन का समय मांगा था उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस फैसले से आगे चलकर जीडीपी में 3% तक की गिरावट आ जायेगी। आज डा. मनमोहन सिंह का कथन शत प्रतिशत सही सिद्ध हुआ है। जीडीपी में आयी गिरावट से अब तक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष में करीब एक करोड़ लोग बेरोज़गार हो गये हैं। जमा धन और ऋण दोनो पर ब्याज दरें कम हुई है लेकिन इसके बावजूद निवेश के लिये कोई आगे नही आ रहा है। आर्थिक मंदी से मंहगाई और बढ़ गयी है। जिन लोगों का रोज़गार छिन गया है उन्हें जीवन यापन चलाने में कठिनाई आ रही है। इसी सबका परिणाम है कि आज माननीयों के वेत्तन/भत्ते और पैन्शन तथा अन्य सुविधाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। इसी याचिका का परिणाम है कि सांसदों के वेत्तन भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव एक कमीशन को भेजने की बात आयी है। आज जिस तरह की आर्थिक मंदी में देश पहुंच गया है उसके लिये इन माननीयों के अतिरिक्त और दूसरा कोई जिम्मेदार नही है।

आज हिमाचल की स्थिति राष्ट्रीय स्थिति से भी दो कदम आगे पहुंच चुकी है। सरकार ने कर्ज और रोज़गार को लेकर सही आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने नहीं रखे हैं। विधानसभा में आये लिखित आंकड़ों के बाद भी जब गलतब्यानी की जायकगी तो उसका असर सरकार की विश्वसनीयता पर पड़ेगा ही। इसी का परिणाम है कि जब पर्यटन निगम की परिसंपत्तियों को लीज पर देने की योजना सार्वजनिक हो गयी तो मुख्यमन्त्री को यह कहना पड़ा कि यह सब उनकी जानकारी के बिना हुआ है। इस पर जांच की बात करते हुए सचिव पर्यटक को बदल दिया गया। मुख्य सचिव को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये गये हैं। आज मुख्य सचिव प्रदेश से चले भी गये हैं परन्तु यह रिपोर्ट सामने नही आयी है। क्योंकि जब यह मसौदा तैयार हुआ था तब इसकी प्रैजेन्टेशन मुख्य सचिव और मन्त्री परिषद के सामने भी दी गयी थी। उस पर कुछ अधिकारियों और मन्त्रीयों की टिप्पणीयां भी की हुई हैं ऐसे में इसके लिये किसी एक अधिकारी को दर्शित करना कैसे संभव हो सकता है। इस तरह के कृत्य जब आम आदमी के सामने आयेंगे तो वह सरकार पर कैसे विश्वास बना पायेगा। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनके कारण जनता का सरकार पर से विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में जनता के सामने जब भी यह आयेगा कि विधायक और मंत्री इस तरह से अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा ही। आज जनता को एक मौका मिलना चाहिये जहां वह अपने रोष को इस तरह से जुबान दे सके। आज जनता जो भत्ता बढ़ौत्तरी का इस तरह से मुखर विरोध कर रही है वह केवल राज्य सरकार के खिलाफ ही नही वरन् अपरोक्ष में केन्द्र की नीतियों के भी खिलाफ है और इस विरोध के परिणाम दूरगामी होंगे।

भाषा किसी देश की सांस्कृतिक समृद्धि की सूचक होती है

–डॉ कामिनी वर्मा–

वैचारिक सप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। धरती पर जब से मनुष्य का अस्तित्व है तभी से वह भाषा का प्रयोग कर रहा है। ध्वनि एवं संकेत दोनों रूपों में वैचारिक आदान–प्रदान होता रहा है। भारत भाषा और बोलियों की दृष्टि से समृद्ध देश है। भारत के लिए कहा जाता है कि

'कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी'

यहाँ अनगिनत भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। वर्तमान में लगभग 780 भाषाएं व 2000 बोलियां प्रचलित है। भाषा और बोली देश की सांस्कृतिक समृद्धि की सूचक होती है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जैसे जैसे जीवन परिवर्तित होता है वैसे वैसे सांस्कृतिक मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। मनुष्य का जीवन स्तर, आचार–विचार, रहन –सहन में बदलाव का प्रभाव भाषा व बोली पर भी पड़ता है। पिछले 50 वर्षो में भारत में 220 भाषाएं प्रचलन से बाहर हो गई और आगे आने वाले 50 वर्षो में 150 भाषाएं समाप्त होने के कगार पर हैं।

भाषा का राष्ट्र की एकता, अखंडता व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रभाषा देश को भावनात्मक व सांस्कृतिक रूप से संगठित करने में सहायक होती है। प्राचीन काल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक समस्त सांस्कृतिक तथा धार्मिक चर्चा व वैचारिक आदान–प्रदान संस्कृत भाषा में होता था।

विदेशी आक्रमण व अपनी क्लिष्टता के कारण इसका महत्व न्यून हुआ और हिंदी वैचारिक अभिव्यक्ति की भाषा बनी। इसका सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता, अखंडता व सांस्कृतिक समृद्धि में अमूल्य योगदान है। यह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है। न सिर्फ हिन्दू बल्कि मुस्लिम साहित्यकारों, मालिक मुहम्मद जायसी, रसखान, ताज, रहीम ने भी इसके संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है। हिंदी के विषय मे अमीर खुसरो जो ''तूतिये हिन्द'' के नाम से भी विख्यात है, कहते हैं ''चूं मत तती हिदं अर रास्त पुरसी, जे मन हिन्दवी पुरस ता नग्ज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की 'तूती' हूँ।' 'अगर मुझसे सच पूछते हो तो हिंदी में पूछो जिससे मैं कहीं' 'अच्छी बातें बता सकूं'

वास्तविकता भी यही है अपनी मूल भाषा में ही बेहतर वैचारिक सम्प्रेषण सम्भव है। हिंदी भाषा पढ़ने, लिखने व बोलने में सहज व सरल है तथा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। यह उदार भाषा है जिसने अन्य भाषाओं के अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उनके मूल रूप में ही आत्मसात कर लिया। देश में 65 प्रतिशत हिंदी भाषी जनसंख्या है, लगभग हर प्रान्त के लोग हिंदी जानते व समझते हैं। अन्य भाषाओं के समान हिंदी का भी विज्ञान है।

किंतु आज अपने ही देश मे हिंदी उपेक्षित व पिछड़ेपन का दंश सहन कर रही है। औपनिवेशिक काल मे ब्रिटिश सत्ता ने देश को राजनैतिक रूप को गुलाम बनाने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति पर भी प्रहार किया। उनकी भाषा अंग्रेजी थी अत: व्यापारिक, राजनीतिक व व्यवहारिक कार्यो के लिए उन्होंने रंग व रक्त से भारतीय परन्तु सोच, रुचि, नैतिकता व बुद्धि से अंग्रेज परस्त वर्ग तैयार किया। थोड़ी सी अंग्रेजी जानने वाले को नौकरी व अन्य तरह की सुविध ाएं प्रदान की। यहीं से हिंदी के दुर्दिन प्रारम्भ हो गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जून 1946 में गांधी जी ने भारत के स्वतंत्र होने के छ: माह के बाद सम्पूर्ण देश के कामकाज हिंदी में होने की बात कही थी, परंतु आजादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश संस्थानों में कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का स्थान देकर इस भाषा को सुधारने का प्रयास किया। किंतु 1960 में दक्षिण में हिंदी हटाओ, उत्तर में अंग्रेजी हटाओ अभियान ने हिंदी की क्षति की, साथ ही तकनीकी विषयों पर हिंदी में शब्दावली व पुस्तकें न होने के कारण भी हिंदी का गौरव न्यून हो रहा है। कर्नाटक (बंगलूरू) के डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल की शोध रिपोर्ट में हिंदी को विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताया गया है तथा विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिये कार्य कर रहे ग्वालियर के आचार्य राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा ने भी अपने विश्वविख्यात ग्रन्थ 'श्रृंखला' के प्रथम खंड में इसे सही माना है। विश्व की सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद हर जगह अंग्रेजी प्रभावी है। अंग्रेजी भाषा को बोलना व सीखना अपेक्षाकृत कठिन होने के कारण 'हिंग्लिश' को प्रश्रय मिल रहा है, जिसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी के वाक्य शामिल हैं।

हिंदी के उत्थान के लिये 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस व हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। यूनेस्को का भी मानना है भाषा सिर्फ संपर्क, शिक्षा व विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है, तथा उसकी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का कोष है। भाषा के इसी महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ''यूनेस्को ने 2019 को स्वदेशी भाषाओं के वर्ष के रूप मे मना रहा है'' परंतु समाज व सरकार की उपेक्षा के कारण हिंदी अपने राजभाषा के गौरव से बहुत दूर है। हिंदी हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। अत: पूरी निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प से हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए ठोस प्रयास करने व उन्हें कार्यरूप में परिणित करने की आवश्यकता है।

''अंग्रेजी पढ़के जदपि, सब गुण होत प्रवीण'
'पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।''
जय हिंदी, जय हिंदुस्तान

कहीं आने वाली मंदी का कारण हम तो नहीं बनने वाले?

इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की आहट की चर्चा है। भारत के विषय में अगर बात करें तो हाल ही में जारी कुछ आंकड़ों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अप्रैल- जून तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% रह गई है जो कि पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। एक अर्थशास्त्री के लिए ये आंकड़े मायने रखते होंगे लेकिन एक आम आदमी तो साधारण मनोविज्ञान के नियमों पर चलता है। सरकार कह रही है कि आने वाली वैश्विक मंदी का भारत में कोई खास असर नहीं होने वाला है अपितु इसके साथ ही इस वैश्विक मंदी का असर भारत पर नहीं हो इस के लिए अनेक उपाय भी कर रही है।, लेकिन टीवी और अखबार 'आने वाली' मंदी की खबरों और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के 'शस्त्रार्थ' से भरे हैं। तो सोशल मीडिया के मंच पर इस विषय में परोसे जाने वाली जानकारी से आज आम आदमी आश्वस्त होने के बजाए चिंतित एवं भ्रमित अधिक हो रहा है। जो आम आदमी कुछ सालों पहले तक देश की आर्थिक स्थिति से अनभिज्ञ अपने घर की मंदी दूर कर अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगा रहता था आज देश की अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श कर रहा है। पहले उसे मंदी का पता तब चलता था जब मंदी के चलते उसकी नौकरी चली जाती थी या उसके व्यापार में मद्दा आता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के चलते उसे मंदी आने से पहले ही 'मंदी की आहट' का एहसास हो गया है। जाहिर है ऐसे माहौल में जब देश में मंदी को लेकर आए दिन टीवी चैनलों पर डिबेट चलती हो तो देश एक असमंजस की स्थिति का सामना करता है और आम आदमी आने वाले 'मुश्किल समय' के लिए खुद को तैयार करने लगता है। साधारण से साधारण समझ वाला व्यक्ति भी ऐसी परिस्थितियों में कम खर्च और अधिक बचत के लिए ही अग्रसर होगा। इसी मनोविज्ञान के चलते धीरे धीरे बाजार में खपत कम होनी शुरू हो जाती है।

–डॉ. नीलम महेंद्र–

जब खपत नहीं होती तो उत्पादन धीमा पड़ जाता है और ऐसा ही एक चक्र चल निकलता है। अर्थशास्त्र के लिहाज से निवेश का आर्थिक विकास में अहम योगदान होता है। इसीलिए सरकार ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक

सुधार के लिए कदम उठाती है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को अनेक छूट और सुविधाएँ देने की घोषणा करती है ताकि वो व्यापार में निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान दें। मान लीजिए कि सरकार की नीतियों से निवेश शुरू हो जाता है लेकिन खपत फिर भी नहीं होती क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं,

1. बाजार में मौजूद उपभोक्ता यानी आम आदमी के ज़ेहन में मंदी की आहट घर कर गई है तो वो बचत करता है और बाजार में उत्पाद होते हुए भी उसे नहीं खरीदता।

2. वाकई में मंदी है और उपभोक्ता के हाथ में पैसा ही नहीं है।

यानी दोनों ही परिस्थितियों में निवेश तो है लेकिन खपत नहीं।

अब सरकार खपत बढ़ाने के लिए उपभोक्ता के हाथों में पैसा देने के उपाय करती है जैसे टैक्स में छूट, सस्ते ऋण, ब्याज दरों में कटौती आदि।

लेकिन जब मंदी की आहट का मनोविज्ञान देश में फैला हो तो आर्थिक सुधार भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाते। इसलिए सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि किन्हीं दो देशों की अर्थव्यवस्था के हालात एक जैसे नहीं होते। अगर यूरोप या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किसी कारण से मंदी आ रही है तो जरूरी नहीं कि भारत में भी वही स्थिति और कारण उत्पन्न हो। रही आंकड़ों की बात तो भारत में गिरती जीडीपी के हवाले से मंदी की बात की जा रही है तो पहले जीडीपी को समझ लें। दरअसल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है कि एक साल में उस देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है। गिरती जीडीपी का अर्थ है कम उत्पादन। हालांकि अकेली जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का सही आँकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उन अनेक मापदंडों में से एक मापदंड है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं। क्योंकि वो केवल उस देश के सकल उत्पादन के विषय में जानकारी देती है उस देश की खपत या नागरिकों की आय के बारे में नहीं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाल में जो जीडीपी की यह विकास दर 5% की बताई गई है वो केवल इस वर्ष के तीन महीनों की है न कि साल भर की। अब अगर उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ उत्पादन कम हुआ है तो वो हैं, रीयल एस्टेट, टेक्सटाइल, कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और वाहनों के गिरते कारोबार के साथ फाइनेंस कंपनियाँ। इन क्षेत्रों की गिरती जीडीपी के विषय में बात करने से पहले एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि वर्तमान में बाजार में नकद प्रवाह नोटबन्दी के बाद 17% ज्यादा है यानी लोगों के पास पैसा तो है लेकिन बाजार में खपत नहीं है। अब अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरती जीडीपी को समझें तो यहां उत्पादन कम हुआ है क्योंकि मांग कम हुई क्योंकि सरकार ने आने वाले समय में प्रदुषण कम करने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। जाहिर है लोग अब नई टेक्नोलॉजी और भविष्य में निवेश करना चाहेंगे। रियल एस्टेट की बात करें तो 2014 से पहले रियल एस्टेट में सब जानते हैं निवेश कहाँ से आता था नोटबन्दी के बाद इसमें आने वाली मंदी अपेक्षित ही थी। इस क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए गृह ऋण और ब्याज दर कम किए जाते हैं। कृषि जगत तो विगत कई वर्षों से नीतिगत सुधारों की अपेक्षा कर रहा है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्र, विधिक सेवा क्षेत्र, शिक्षा जैसे क्षेत्र सफलता पूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की डोर मजबूती से थामे हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ रही है और देश के आम आदमी के मनोविज्ञान पर नकारात्मकता का संचार करेगी। बेहतर होगा कि अभी समय को अपनी चाल चलने दें और इंतजार करें यह देखने के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठती है।

कौशल विकास से रोजगार सृजन

प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। इस समय प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास परियोजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के लगभग एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाएगा।

कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया। 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। लगभग 2340 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण पूरा किया गया, 341 प्रशिक्षुओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

कौशल विकास निगम के सहयोग से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक (वोकेशनल) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017 – 18 में 824 तथा वर्ष 2018 – 19 सत्र में 1010 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

कौशल विकास निगम द्वारा चयनित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'ग्रेजुएट एड – ऑन' कार्यक्रम आरम्भ, जिसमें इस सत्र में 750 विद्यार्थी शामिल हुए। 28 मार्च, 2018 को एशियन विकास बैंक के साथ 650 करोड़ रुपये की 5 वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस परियोजना के तहत 53 हजार से भी ज्यादा युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, 50 आई.टी.आई. स्तरोन्नत की जाएगी, 6 शहरी आजीविका केन्द्र तथा 7 ग्रामीण आजीविका केन्द्र खोले जाएंगे। एशियन विकास बैंक के सहयोग से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में 7 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

एशियन विकास बैंक की इस परियोजना के अंतर्गत निगम द्वारा आदर्श कैरियर केन्द्र, हमीरपुर, राजकीय महिला तकनीकी महाविद्यालय, कांगड़ा, शहरी आजीविका केन्द्र, शमशी, शहरी आजीविका केन्द्र, सुन्दरनगर तथा शहरी आजीविका केन्द्र, नाहन के निर्माण कार्य आरम्भ किए।

मंडी जिले में ग्रामीण आजीविका केन्द्र, सदयाना, शिमला जिला के ग्रामीण आजीविका केन्द्र, चौपाल तथा प्रगतिनगर के निर्माण कार्य भी आरम्भ किए गए।

77 करोड़ रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी लागू की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 21.56 करोड़ रुपये की पहली किश्त प्राप्त। इससे लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार सम्बन्धी कौशल प्रदान किया जाएगा।

सभी रोजगार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्रों तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं के लिए परामर्श के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे।

ग्रामीण महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कराना, उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे उन्हें अवगत करवाने तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई सशक्त महिला योजना आरम्भ की गई है।

इन सभी कौशल विकास गतिविधियों से राज्य के युवाओं को रोजगार और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे।

12 अध्यापक राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

शिमला/शैल। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में वर्ष 2019 के 12 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग समय की मांग है, लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि आत्मिक सम्बन्धों को हर कीमत पर बनाए रखा जाए।

यह शिक्षकों पर निर्भर करता है कि वह विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता पर बल दें ताकि भारतीय संस्कृति के अनुरूप अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की सोच थी।

उनका कहना था कि शिक्षक ज्ञान का स्त्रोत और समवाहक होते हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति के अनुरूप नैतिक संस्कार देने और गुणात्मक शिक्षा को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को सम्मानित किया गया, निश्चित तौर पर उन्होंने गुणात्मक शिक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य एक शिक्षक कर सकता है। यही आत्मविश्वास जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन् ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया और उनका मानना था कि नैतिकता से ही अनुशासन आता है।

राज्यपाल ने कहा कि अभिभावक के बाद बच्चों को अपने शिक्षकों से संस्कार मिलते हैं, जो अपने शिक्षकों का गंभीरता से अनुसरण करते हैं। शिक्षक के व्यवहार और संस्कार का प्रभाव परोक्ष रूप से बच्चों पर पड़ता है और यही संस्कार बाद में उनकी पहचान बनते हैं। इसलिए, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक तीनों का अंतरसंबंध बनता है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने

का कार्य निष्ठापूर्वक करें। उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करें, क्योंकि पढ़ने से विचारशीलता आती है और नवाचारों का उदय होता है।

कलराज मिश्र ने कहा कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना शिक्षा का आधार होना चाहिए। बच्चों का विकास इस रूप में आवश्यक है कि वे बड़े होकर सशक्त राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।

पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए उन्होंने शिक्षक समुदाय का आहवान किया कि वे अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें ताकि गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ- साथ वे अपने विद्यार्थियों को उच्च नैतिक मूल्य व संस्कार दे सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बहुत जिज्ञासु होते हैं और बचपन में उन्हें जो सिखाया-बताया जाता है, उसका प्रभाव जीवनभर रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक उनके लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनें और उनमें अध्ययन, सदाचार व अनुशासन की भावना जागृत करें। इसके साथ ही युवा पीढ़ी को हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली इतिहास के बारे में भी जागरूक करना भी शिक्षकों का उत्तरदायित्व है ताकि उनमें राष्ट्र भक्ति व स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हो।

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यद्र की कि हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी तरक्की की है और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें शिक्षकों का बड़ा योगदान है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि 5 सितम्बर का दिन डॉ. एस. राधाकृष्णन से जुड़ा है जो एक महान दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद् थे। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन एक दक्ष वक्ता, सफल कूटनीतिज्ञ, प्रशासक, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और प्रख्यात लेखक थे, जिनके लिए शिक्षा एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक मिशन था जिसे प्रति वह पूरी तरह समर्पित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनका जन्म दिन शिक्षक दिवस के रुप में मनाते हैं ऐसे में यह समझना यह आवश्यक है कि शिक्षा के बारे में उनकी सोच व दृष्टिकोण को समझा जाए। शिक्षा से उनका अभिप्राय व्यक्तिगत तौर पर और विश्व स्तर पर एकीकरण है ताकि व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बन सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा लोगों को अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ध्येय लोगों को समाज की कार्यप्रणाली को समझने में सशक्त बनाना होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को डिग्री हासिल करने और रोजगार देना है, बल्कि यह युवाओं में अनुसंधान की भावना, तर्कसंगत सोच को विकसित करके उन्हें समाज में हो रहे बदलावों व कर्मियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है।

उन्होंने शिक्षक वर्ग का आह्वान किया कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अपना सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही छात्रों को नैतिक शिक्षा देकर एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय और पोर्टमोर स्कूल शिमला की छात्राओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए 31-31 हजार रुपये देने की घोषणा की। जिन्होंने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पन्त ने शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोहित जम्वाल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

स्कूली विद्यार्थियों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थीगण इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक

1. यजनीश कुमार, प्रवक्ता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जन्दूर, जिला हमीरपुर

2. सत्यपाल सिंह प्रवक्ता व.मा. पा कण्डाघाट जिला सोलन

3. सन्तोष कुमार चौहान, डीपीईए व.मा.पा समरहिल जिला शिमला

4. नेत्र सिंह टीजीटी, व.मा.पा कमान्द, जिला मण्डी

5. नन्द किशोर शास्त्री व.मापा. कुनिहार, जिला सोलन

6. जितेन्द्र मनहास जेबीटी प्राथमिक पाठशाला नेरी, जिला ऊना

7. विजयपुरी जेबीटी, प्राथमिक पाठशाला खारटी, जिला कांगड़ा

8. नारायण दत्त जेबीटी प्राथमिक पाठशाला लाणा मियूता जिला सिरमौर

9. आशा राम जेबीटी प्राथमिक पाठशाला नन्द जिला बिलासपुर

10. प्रदीप मुखिया जेबीटी प्राथमिक पाठशाला रोहडू जिला शिमला

11. युद्धवीर जेबीटी प्राथमिक पाठशाला सुन्दला जिला चम्बा

12. नरेश कुमार टीजीटी माध्यमिक पाठशाला, सिराज-2 जिला मण्डी।

स्नेहलता ने स्वरोजगार से दिखाई आर्थिक स्वावलंबन की राह

कांगड़ा जिला के धर्मशाला तहसील में स्थित है नन्देहड़ गांव। इस गांव की स्नेहलता ने दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वास के बूते अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी मेहनत द्वारा किये जा रहे कार्य के कारण वे और लोगों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनी हुई हैं।

स्नेहलता ने जिदंगी की तमाम

बाधाओं को पार करते हुए अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदल डाला है और एक नई सामाजिक पहचान बनाई है। बाहरवीं कक्षा तक पढ़ी 33 वर्षीय स्नेहलता करीब 10 साल पहले विवाह कर जब नन्देहड़ गांव में अपने ससुराल आई थीं, उस समय घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्नेहलता के परिवार का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी एवं सब्जी उत्पादन है। उन्होंने अपने परिवार के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया, लेकिन नकदी फसलें लगाने की जानकारी एवं ज्ञान के अभाव में उनके प्रयास बहुत सफल नहीं रहे। ऐसे में स्नेहलता को पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नन्देहड़ में लगाए गये जागरूकता शिविर से संस्थान के द्वारा करवाए जाने वाले नि:शुल्क प्रशिक्षण कायक्रमों की जानकारी मिली। स्नेहलता इस जागरूकता शिविर से प्रेरित हुई जिससे उसने अपने गांव की महिलाओं को संस्थान द्वारा उनके गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने संस्थान से गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आग्रह किया। संस्थान द्वारा कुछ समय के पश्चात उनके गांव में सब्जी नर्सरी प्रबंधन एवं उत्पादन की ट्रेनिंग शुरू करवाई गई।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। जिससे उन्हें पता चला कि सब्जी की खेती कैसे की जाती है व सब्जी में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए तथा सब्जी के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

स्नेहलता बताती हैं कि उनके लिए यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नकदी फसलों की खेती करने की विधि के बारे में भी पूरी जानकारी ली।

स्नेहलता बताती हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने 10 हजार रूपये की पूंजी लगाकर सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। इसके उपरांत हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा मटौर से 50 हजार रुपये का ऋण लिया। मेहनत और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान के बूते देखते ही देखते दिन बदलने लगे। आज वे सब्जियों को पास की ही दुकानों में बेच देती हैं तथा कुछ सब्जियां को सब्जी मंडी धर्मशाला में भेज देते हैं। इस तरह वह हर महीने लगभग 8 हजार रूपये कमा रही हैं।

स्नेहलता के पति रघुवीर सिंह का कहना है कि स्नेहलता के आत्मविश्वास ने उनके परिवार की जिन्दगी बदल दी है। पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक महेन्द्र शर्मा बताते हैं कि संस्थान जरूरतमंद एवं इच्छुक लोगों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण देता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर हो सकें। वे बताते हैं कि संस्थान 18 से 45 वर्ष तक की महिलाओं और पुरूषों को डेयरी फार्मिंग, खुम्ब उत्पादन, सब्जी नर्सरी प्रबंधन और सब्जियों की खेती, आलू एवं प्याज की खेती और प्राकृतिक संरक्षण, अचार और पापड़ बनाना, खिलौने बनाना, डुने पत्तल बनाना, कपड़े के बैग बनाना तथा मोबाईल रिपेयरिंग जैसे विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा वे स्वरोजगार हेतु जिला कांगड़ा के किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि सभी जिलावासियों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। प्रशासन के इन प्रयासों में पंजाब नैशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो बेहद सराहनीय है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से लोग क्षेत्र विशेष के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर एवं कौशल विकास से स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ें हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन लोगों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब लाला लाजपत राय के नाम से जाना जायेगा धर्मशाला कारागार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जिला कारागार (ओपन एयर) भवन के धरातल व प्रथम मंजिल की आधारशिला

रखी। इस अतिरिक्त भवन के निर्माण को 82 लाख रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा जिसमें आगंतुक कक्ष, शस्त्रागार, सीसीटीवी/ निगरानी कक्ष, उप पुलिस अधीक्षक कक्ष, स्टोर, पैन्टरी, पैरा-लीगल कार्यालय तथा रिकार्ड कक्ष आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कारागार परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा का अनावरण किया। लाला लाजपत राय को 21 अप्रैल, 1922 से 9 जनवरी 1923 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कारागार में रखा गया था। उन्होंने इस कारागार का नामकरण लाला लाजपत राय करने की घोषणा की।

इससे पूर्व धर्मशाला पहुॅचने पर जिला के नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।

APPEAL

H. P. State Pollution Control Board solicit the active participation of all the educational institutions, NGOs, commercial establishments and general public in the campaign for abatement of water pollution of rivers/nallah/waterbodies of Himachal Pradesh.

Following **seven river stretches** of Himachal Pradesh have been identified as **polluted** river stretches

Priority based on pollution load = Priority-I (BOD ≥ 30 mg/L), Priority-II (BOD=20-30 mg/L), Priority - III (BOD=10-20 mg/L) & Priority - V (BOD=03-06 mg/L)

- **Sukhana Nallah (Priority-I)**
  (Sukhna to Parwanoo) District – Solan.
- **Markanda River (Priority-II)**
  (Kala Amb to Narayanpur) District – Sirmour.
- **Sirsa River (Priority-III)**
  (Nalagarh to Solan) District – Solan.
- **Ashwani River (Priority-V)**
  (Along Yashwant Nagar) Districts – Shimla, Solan.
- **Beas River (Priority-V)**
  (Kullu to Dehragopipur), Districts- Kullu, Mandi, Hamirpur, Kangra.
- **Giri River (Priority-V)**
  (Along Sainj) District- Shimla.
- **Pabbar River (Priority-V)**
  (Along Rohru) District- Shimla.

Visit us at

https://hppcb.nic.in/

Click on e-suggestion tab and share your valuable suggestions/ post your comments & complaints for making our waterbodies pollution free.

Your **suggestions** are **welcome!**

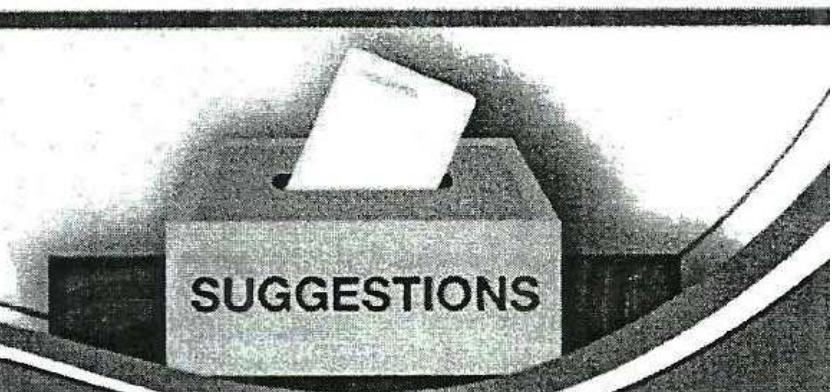

H. P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Him Parivesh, Phase-III, New Shimla -171009

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उपचुनाव किसके काम की परीक्षा होंगे–मोदी या जयराम

बढ़त का अनुपात बनाये रखना होगी कसौटी

शिमला/शैल। प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला और पच्छाद में उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहां के विधानसभा सांसद बनकर जा चुके हैं। इसके बाद मन्त्रीमण्डल में भी दो मंत्री बनाये जाने हैं। क्योंकि किशन कपूर और अनिल शर्मा द्वारा खाली किये गये पद अभी तक भरे नही गये हैं। जयराम सरकार बनने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब जनता में वोट मांगने जाना पड़ेगा। पहला मौका था लोकसभा के चुनाव और उनमें केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की प्रतिष्ठा दाव लगी हुई थी। बल्कि मुख्यमन्त्री ने मन्त्रीयों के खाली पदों को भरने के लिये लोकसभा चुनावों मे परफारमैन्स का पैमाना लगा दिया था। लेकिन लोकसभा में जिस अप्रत्याशित बढ़त के साथ भाजपा ने प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल की है उससे परफारमैन्स की शर्तें एकदम हाशिये पर चली गयी है। ऐसे में यह उपचुनाव ही सही मायनों में परीक्षा होंगे और इसमें लोकसभा वाली बढ़त का अनुपात बनाये रखना ही कसौटी होगा। क्योंकि अभी जिस तरह वातावरण बना हुआ है उसमें हार या कड़ी टक्कर जैसी कोई संभावना दूर-दूर तक नही है। बल्कि ऐसा तभी संभव होगा जब अपने ही कार्यकर्ता और नेता सरकार को आईना दिखाने की रणनीति पर न आ जायें।

'' यह आईना दिखाने '' जैसा सन्देह क्यों है इसके संकेत इन उपचुनावों में टिकटार्थीयों की लंबी होती सूची और कांग्रेस के घर में सेंध लगाकर कुछ छोटे बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल करने से उभरे हैं। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और फिर मुनीष शर्मा के नामों की चर्चा आना इसके प्रमाण हैं। इन नामों से हटकर पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल को उम्मीदवार बनाये जाने की मांग नगरोटा और ज्वालामुखी मण्डलों के प्रस्तावों से आना एक बड़ी राजनीतिक हलचल थी। क्योंकि धूमल का नाम आते ही धर्मशाला के कुछ गैर राजनीतिक मंचों द्वारा यह प्रतिक्रिया देना की धर्मशाला को राजनीतिक धर्मशाला नही बनने देंगे एक बड़ी ही सुनियोजित राजनीतिक रणनीति थी। लेकिन जिन मंचों से यह प्रतिक्रिया आयी बाद में उन्ही से जुड़े कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही दावेदारी आगे करने का कदम उठा लिया। क्योंकि इनमें से कई लोग जो जनसंघ के जमाने से संगठन से जुड़े हुए हैं यही नहीं कर्मचारियों में डॉ. अरविन्द कन्दौरिया और सेवा निवृत अधिकारी डॉ. रोकश कपूर तक के नाम धर्मशाला के गलियारों में चर्चा में चल रहे हैं। इस चर्चा के लिये इन लोगों के आरएसएस से संबंध सबसे बड़ा तर्क बने हुए हैं। स्मरणीय है कि जब 2017 में पालमपुर में भाजपा का बुद्धिजीवि सम्मेलन हुआ था जिसे अमितशाह ने संबोधित किया था उसमें डॉ. राकेश कपूर ही अकेले कार्यरत अधिकारी थे जिन्हें उसमें विशेषरूप से बुलाया गया था। ऐसे कई प्रसंग चर्चा में हैं।

लेकिन इसी के साथ यह भी सत्य है कि लोकसभा चुनावों में जब किशन कपूर को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया था तब उनके बेटे को विधानसभा का टिकट देने की बात की गयी थी। इसी तरह पिछले दिनों जिस तरह से त्रिलोक कपूर की प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चर्चा में आया है उससे उनकी उम्मीदवारी का दावा भी गणना में आ गया है। इस तरह करीब आधा दर्जन नाम उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इन सारी चर्चाओं के साथ एक बड़ा सवाल यह उछल रहा है कि धर्मशाला की प्रशासनिक सेहत कैसी है क्योंकि पिछले दिनों जब नगर निगम का एक जेई एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है उसके बाद किशन कपूर तक को यह कहना पड़ा कि धर्मशाला में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। प्रशासनिक सेहत के साथ ही धर्मशाला से जुड़े कुछ विकास के सवाल भी चर्चित होने लग पड़े हैं। सवाल उठ रहा है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय दस वर्ष बाद भी केवल शिलान्यास तक ही क्यों पहुंचा है। हाईकोर्ट की सर्किट बैंच की मांग लम्बे अरसे से लटकी पड़ी है। बल्कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने से यह सवाल और भी बड़ा बन गया है। इस तरह के कई और मुद्दे पार्किंग, बस अड्डे की दुर्दशा और पर्यटन विकास के लिये आधारभूत ढांचा विकसित करने के नाम पर कोई बड़ा काम न होना इस उपचुनाव के महत्वपूर्ण स्थानीय सवाल होंगे।

परन्तु इन सारे सवालों से भी भारी पिछले दिनों शान्ता कुमार के नाम लिखा गया एक कार्यकर्ता गुमनाम पत्र है। इस पत्र में कुछ गंभीर मुद्दे उठाये गये हैं एक तरह से भ्रष्टाचार की ओर ध्यान खींचा गया है। इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि लिखने वाले के पास काफी अन्दर तक की जानकारीयां हैं। सोशल मीडिया में इस पत्र के चर्चा में आने के बाद ही मुख्यमन्त्री और शान्ता कुमार में बन्द कमरे में बैठक हुई और उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार को शामिल नही किया गया जबकि वह धर्मशाला से पालमपुर मुख्यमन्त्री के साथ गये थे और बैठक के दौरान भी होटल यामिनी में ही मौजूद थे। जयराम-शान्ता की इस मुलाकात के बाद शान्ता कुमार की ओर से एक प्रतिक्रिया भी आयी है। शान्ता कुमार के नाम एक गुमनाम कार्यकर्ता का पत्र और मुख्यमन्त्री से मुलाकात के बाद आयी प्रतिक्रिया यथास्थिति पाठकों के सामने रखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सब इन उपचुनावों में चर्चा के विषय रहेंगे और बहुत संभव है कि कुछ और भी समाने आये।

शान्ता के नाम एक कार्यकर्ता का पत्र

आदरणीय शान्ता कुमार जी,
प्रणाम,

'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' इस कहावत का असली मतलब तब समझ आया जब मैंने आपकी लिखित पुस्तक 'भ्रष्टाचार का कड़वा सच' को पढ़ा।

क्या वह किताब केवल गत भाजपा सरकार को रिपीट न होने देने के उद्देश्य से लिखी गयी थी या फिर आप सच में ही देश और प्रदेश की जनता को सरकारों में पनपते भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना चाहते थे? अगर आप वास्तव में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और आज भी हैं तो आज जो आपके नाक के तले हो रहा है उसके प्रति आप चुप क्यों हो? क्यों जानबूझ कर गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है? क्या आप भ्रष्टाचार के हो रहे नंगे खेल से अवगत नही है? या फिर जानबूझ कर केवल मात्र इसलिए अनजान बने हुए हैं कि इस बार भ्रष्टाचार करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की जनता में आपकी छवि एक ईमानदार नेता की रही है पर आज ये तथाकथित ईमानदार आवाज ने अपने मुंह को क्यों सिल लिया है।

शांता जी, आपने जेनेरिक दवाईयों के नाम पर लंबी लड़ाई लड़ी। जनता जानना चाहती है क्या वह लड़ाई मात्र इसलिए थी कि सत्ता में आपका प्रिय शिष्य स्वास्थ्य मंत्री बनते ही अपने मित्रों को सरकारी अस्पतालों में उन दवाईयों की सप्लाई का आर्डर दे। और उनके प्रिय मित्र दवाईयों के नाम पर जो 'भस्म भबूत' मैडिकल कॉलेज सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं उससे गरीबों की जो हाय लगेगी उससे तो शायद ही भगवान उनको बचाएगा। पर आपकी शाख को लगा बट्टा शायद ही मिट पायेगा। अगर आपको विश्वास नही है तो अपने सामने पड़े फोन से प्रदेश के किसी भी प्रसिद्ध डॉक्टर को वर्तमान में सप्लाई हो रही तथाकथित जेनेरिक दवाईयों की क्वालिटी के बारे में पूछें?

क्या यह भ्रष्टाचार नही कि स्वास्थ्यमंत्री और मुख्यमंत्री का एक करीबी सरकार बनने के बाद 35 करोड़ की दवाइयां सप्लाई कर चुका है और स्वास्थ्य विभाग की एक गाड़ी हमेशा उसके घर के बाहर खड़ी मिलती है। और विभिन्न सी एम ओ को बाकायदा फोन करके उनसे दवाईयां खरीदने का दबाव डाला जाता है।

प्रिय शांता जी, आयुर्वेद विभाग में मंहगी खरीद में आईएएस भटनागर को दोषी मानकर उस पर दिखावे के लिए छोटी सी कार्यवाही करके जनता की आंखों में धूल तो झोंक दी परन्तु जिस विपिन परमार के आदेश पर यह खरीद हुई उनके खिलाफ कौन कार्यवाही करेगा? क्या इस पर भी आपको भ्रष्टाचार नही दिखाई देता है?

पिछले डेढ़ वर्षो में कई दवाईयों के सैंपल फेल हुए पर आज तक कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट नही हुई? आखिर क्यों? और आप इसलिए चुप है क्योंकि विपिन परमार आपके खर्चे उठाते हैं?

मन्डी में एक डॉक्टर ने अपने ही बेटे से 2 रुपये की दवाई 16 रुपये में खरीद ली। पर अब आप क्यों बोलेंगे? हर दूसरे दिन अखबारों में छपा मिलता है कि सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाईयां महंगी खरीदी जा रही है और ओपन मार्किट में सस्ती मिल रही है इसका जिम्मेदार कौन है कभी सोचा आपने?

चंद मित्रों ने सिविल सप्लाई की दुकानों से सीधे सीधे कमीशन वसूल किया है आप सब जानते हुए भी चुप हैं। आप सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि पालमपुर हॉस्पिटल की सिविल सप्लाई की दुकान किसके फोन से आवंटित हुई है?

पंजाब में 290 रुपये में बिकने वाला सीमेंट हिमाचल में 390 रुपये में बिक रहा है और सबको मालूम है कि पिछले डेढ़ वर्षो में इसकी कीमत 90 से 100 रुपये बढ़ी है और कीमतों में वृद्धि का कारण मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री की सीमेन्ट कंपनियों के साथ सांठगांठ है। फिर भी आज आपको भ्रष्टाचार नही दिखाई देता।

धारा 118 के तहत कांग्रेस के 1081 स्वीकृतियों के मुकाबले हमने 1 वर्ष में ही 590 दे दी और इसी रफ्तार से चलते रहे तो पांच वर्षो में आधा हिमाचल बिक जायेगा। पर आप क्यों बोलेंगे। क्योंकि अब आपके शिष्य सत्ता में हैं। अब आपको भ्रष्टाचार नही सुशासन दिखाई दे रहा है।

प्रदेश में सबको मालूम है कि पिछले एक वर्ष से पर्यटन विभाग के होटलों को लीज पर देने के लिए सरकार तैयारी कर रही थी और इसके बावत कई बार अखबारों में खबरें भी छपी। और अब जब इन प्रोपर्टी को सेल पर लगाने की आलोचना हुई तो सरकार ने एक निर्दोष अधिकारी को ही दाव पर लगा दिया अपनी खाल बचाने के लिए। जिस हिमाचल को आप स्विट्जरलैंड बनाने की बात करते थे वो आज बिकाऊ हो गया है। जिन सम्पतियों को हिमाचलीयों ने अपने खून पसीने से सींचा था उन्हें आज लूटने की कोशिश की जा रही है।

शांता जी हर दूसरे महीने 500 करोड़ रुपये का कर्जा लिया जा रहा है और उनमें से पैसा सिर्फ सराज विधानसभा को सजाने संवारने में लगाया जा रहा है बाकी हिमाचल के तो जैसे वो मुख्यमंत्री ही नही है। कभी आपने पूछा कि कांगड़ा और चम्बा के विकास के लिए पिछले डेढ़ साल में क्या किया? कब तक आप आँखें बंद रखेंगे? कर्जे की यही हालत रही तो हिमाचल के वजूद पर ही संकट आ जायेगा।

शांता जी, अपनी पीढ़ी के आप और वीरभद्र मात्र दो नेता बचे हैं वीरभद्र अपने केसों से बचने के लिए सरकार के साथ खड़े हो गए हैं परन्तु आप ने जो अपने जीवन भर की कमाई की है वह इन डेढ़ वर्षो में गवाने के कगार पर आ चुके हैं।

आज कोई मुंह से न कहे पर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता कह रहा है कि यह सरकार भाजपा की नही केवल चंद मित्रों की सरकार बन कर रह गयी है। उन मित्रों को यह लगता है कि पता नही किस्मत से मिला यह मौका दूसरी बार आएगा कि नही। इसलिये जितना हो सके दोनों हाथों से लूट लो। आज कांग्रेस कमजोर है इसलिये वो चुप है पर जनता सब देख रही है। कार्यकर्ताओं ने भी खुल कर कहना शुरू कर दिया है कि अफसरों पर पकड़ नही कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं **और आप इसलिए चुप हैं कि आपका लूट के माल का एक हिस्सा आप तक भी पहुंचता है इसलिए आप ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली है।**

इसलिये आपसे विनम्र आग्रह है कि कृप्या आगे से ऐसी कोई किताब न लिखे जिसकी वजह से आपको शर्मिन्दगी उठानी पड़े। केवल वही लिखें जो वास्तव में आप हो।

जो 'अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और था'
एक कार्यकर्ता
जो आपको आदर्श मानता था।

शान्ता-जयराम बैठक के बाद शान्ता की प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद, शान्ता कुमार ने कहा कि वह सोशल मीडिया में बहुत कम कभी-कभी कुछ लिखते है। इस बार 12 सितम्बर जन्मदिन से कुछ पूर्व उन्होने अपने मन की बात कही। उन्हें दुख है कि उनके शब्दों से कहीं-कहीं कुछ गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होने उसे स्पष्ट करना चाहा है।

शान्ता कुमार ने कहा कि वह कई बार कह चुके है कि भारत के राजनैतिक नेताओं में सबसे अधिक सन्तुष्ट और प्रसन्न यदि कोई है तो निश्चित रूप से वह शान्ता कुमार हैं। उन्हें प्रभु ने और पार्टी ने क्या नहीं दिया और उन्होने भी जी भर कर देश और प्रदेश की सेवा की। उन्होंने मीडिया से विशेष आग्रह किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से असन्तुष्ट कह कर उनके साथ अन्याय न करें।

उन्होने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और वैसे भी इस आयु में जवानी की तरह की सक्रीयता नहीं रह सकती और उन्होंने विवेकानन्द ट्रस्ट में और अधिक काम करने का निर्णय किया है। उन्होने कहीं से किनारा नहीं किया न ही कभी करेंगे।

शान्ता कुमार ने कहा कि धर्मशाला उप-चुनाव जीतना हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले लोक सभा चुनाव में वह उम्मीदवार नहीं थे परन्तु पहले से भी अधिक उन्होंने चुनाव में काम किया और जनता ने भी समर्थन का नया रिकार्ड बनाया। कांगड़ा-चम्बा लोकसभा देश में प्रथम रही। धर्मशाला उप-चुनाव ही नही, पार्टी के किसी भी ऐसे काम में उन्हें सबसे आगे पाओगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए हमारा सुझाव होता है। हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होता। उम्मीदवार तो पार्टी का होता है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वहीं उनका भी निर्णय होगा।

शान्ता कुमार ने कहा है कि मंत्रियों के काम-काज के संबंध में विचार और निर्णय लेना केवल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है फिर भी यह सही है कि मंत्री हमारे हैं तो उन्हें उनके संबंध में सब प्रकार की चिन्ता भी रहती है। वे अपने मन्त्रियों से मिलते भी रहते हैं, बात भी होती रहती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर बड़े स्तर पर सेवा सप्ताह मना रही है। उन्होंने उससे पहले ही अपने जन्म दिन पर विवेकानन्द सेवा केन्द्र में सेवा करने का संकल्प किया है। सभी मित्रों को इस बात की विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए।